SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is of a small quantity of 600 tonnes out of more than 7 lakh tonnes.

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास

92. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने की किसी विशेष योजना पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों से निरक्षरता समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). शिक्षा की योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों सहित समाज के उन वर्गों की आवश्यकताओं को, जिन्हें विगत में पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं, उच्चतम प्राथमिकता दी गई है । शैक्षिक विकास की नई नीति के दो मुख्य पहलू हैं, प्रारंभिक शिक्षा का सर्व-व्यापीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार अगले लगभग 5 वर्षों के दौरान 6–14 आयु वर्ग के 3.2 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा कार्य-क्रमों तथा 15–35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ को प्रौढ़ शिक्षा के कार्य-क्रमों के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है । गृह मंत्रालय के संघटित जनजातीय विकास कार्यक्रम में 116 परियोजनाओं के विशेष शैक्षिक विकास कार्य-क्रम शामिल हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : यह जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है इसको प्रक्टिकल शेप कब तक दे दी जाएगी ? प्रदेश सरकारों को इसके अधीन धनराशि कब तक आवंटित की जाएगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस प्रस्ताव के दो पहलू हैं । एक प्रौढ़ शिक्षा का है और दूसरा प्राथमिक शिक्षा के प्रचार का है । प्रौढ़ शिक्षण के बारे में एक नक्शा बन चुका है । इसके अन्तर्गत पांच साल के अन्दर 10 करोड़ अनपढ़ जो प्रौढ़ हैं 15 साल से 35 साल उम्र के बीच के उनके शिक्षण के लिये यह योजना है । दूसरा पहलू जो है उस में हम कोशिश कर रहे हैं तीन करोड़ 20 लाख जो अनपढ़ हैं स्कूल जाने वाले और जो जा नहीं सकते हैं और जिन की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच होगी उनको लिया जाए । राज्य सरकारों से भी इसके बारे में बातचीत चल रही है । जब अगली योजना बन जाएगी तब हम कह सकेंगे कि किस तरह से रुपये को आवंटित करना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अनेक प्रदेशों के पास धन का अभाव है । अनेक ऐसे क्षेत्र आज भी छूटे हुए हैं जहां पर कालेज स्तर की शिक्षा की व्यवस्था भी लगभग न होने के बराबर है । उसकी ओर क्या आप ध्यान देंगे और राज्य सरकारों को विशेष धनराशि आवंटित करेंगे इसके लिए । इस विषय में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यू. पी. के अन्दर रामपुर जिले में 11 परसेंट के लिए ही अभी तक शिक्षा की व्यवस्था है । इस दृष्टिकोण से वहां सरकार को आप अधिक धन देंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : बहुत से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, माननीय सदस्य की यह बात सही है । गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा प्रोग्राम लिया जा चुका है, इंटेग्रेल ट्राइब्ल डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट
These projects have been identified in areas where more than 50 per cent of

the tribal population is concentrated. So far 116 projects have been cleared.

कालेजों के बारे में भी बात उठी है । इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं :

However, the existing scheme of UGC lays stress on development of affiliated colleges in backward areas. The eligibility conditions of student enrolment and staff strength are substantially relaxed. Such colleges are eligible for assistance upto 3 lakh if their student strength is 200 and staff strength 10 whereas in normal conditions the requirement of student strength of 400 and staff strength of 20 is needed.

इससे पता लगेगा कि जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिये कुछ काम हो रहा है और इससे वह फ़ायदा उठा सकते हैं ।

श्री बी० पी० मण्डल : मैं जानना चाहता हूं कि ऐजूकेशनली बैकवर्ड एरिया का सरकार का क्या क्राइटेरिया है ? कितनी लिट्रेसी का परसेंटज नहीं रहने से उस एरिया को लिट्रेरी बैकवर्ड कहते हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वह तो तय नहीं हुआ है । लेकिन जो जनरल ऐवरेज है उससे नीचे होगा तो उसको बेकवर्ड कहा जायेगा ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े क्षेत्रों में निरक्षरता समाप्त कर के साक्षरता प्राप्त करने का दायित्व भारत सरकार पर है । आपने जैसा बताया, राज्य सरकारों के माध्यम से करेंगे । क्या यह सम्भव है कि इतना बड़ा कार्य केवल राज्य सरकारों के माध्यम से ही होगा ? या कोई ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को, जो इस कार्य में लगी हुई हैं या काम करना चाहती हैं, उनको भी भारत सरकार कुछ अनुदान दे कर निरक्षरता समाप्त करने का यास करेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : बात बिल्कुल सही है कि हम सोचते हैं कि केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से यह काम नहीं हो सकता है । इसीलिये हमने मीटिंग बुलायी थी उसमें पार्लियामेंट की पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाया था और

there are trade, industry and employers' organisations, voluntary agencies working in the field of education, youth and students organisations, teachers associations and trade unions. I have called meetings of the representatives of these bodies separately and they have all promised help. We are also to help the voluntary agencies in this field.

DR. KARAN SINGH: Ladakh is one of the most backward areas in the entire country. There was a School of Buddhist studies set up in Ladakh under the Government of India. It was specifically set up in order to see that the culture and the philosophy of that region is developed. But my reports are that it is functioning in a very unsatisfactory manner. Will the hon. Minister kindly let us know whether he is a aware of the functioning of this institute and, if not, whether he will look into it and see that in this very backward and war flung area, the institute really fulfils the purpose for which Jawaharlal Nehru set it up many years ago.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Although the question does not arise out of this, I can assure the hon. Member that this morning I had some discussion with the representatives of the people coming from Ladakh and, in the afternoon again, I have called a meeting with the officers and we will look into the problems raised by them.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Education has been hard hit in the adjoining areas of the border, specially the sensitive areas near the Pakistan border. Will the hon. Minister give an assurance that he will give special consideration to the areas, such as, Amritsar, Ferozepur and Gurdaspur, where due to continuous attacks the education system has been very much hard hit.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As the House is aware, the primary responsibility for the education at the lower stage remains with the State Government. Still, we have accepted the responsibility and we should work hand in hand with the State Government. They are also cooperating and the areas that have been mentioned by the hon. Member will certainly be taken into consideration.

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, जिस गति से भारत सरकार ऐलीमेंटरी और ऐडल्ट ऐजूकेशन प्रोग्राम को फ़ेजवाइज़ चलाना चाहती है उस के अन्तर्गत जो हमारी अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना है और जिस गति से सरकार कर रही है वह कब तक पूरी कर सकेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही कहा कि अभी अनिवार्य शिक्षा को तो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिये जो नक्शा बन चुका है उसमें 3 करोड़ 20 लाख तक बच्चों की औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये हम कोशिश कर रहे हैं । इसके बाद 1 करोड़ 32 लाख जो होंगे उसके लिये इंतजाम करा जायेगा ।

Removal of Restrictions on Movement of Sugar

+

*97. SHRI PRASANNBHAI MEHTA:
SHRI VAYALAR RAVI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that curb on sugar movement has ended;

(b) if so, whether private trader can now despatch or receive sugar from any part of the country;

(c) if so, to what extent the prices of sugar will be reduced;

(d) to what extent they have been reduced; and

(e) whether the free movement would ensure a uniform open market price throughout the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). Yes Sir.

(c) and (d). The withdrawal of restriction on inter-State movement of free-sale sugar on trade account is intended to facilitate movement from principal markets to areas where the volume of local demand is not sufficiently large to ensure direct movement from sugar factories. The prices of free-sale sugar are presently very subdued and have declined by Rs. 70/- per quintal in the last two months.

(e) No, Sir.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: After a long time, the price of sugar has declined. Now, the sugar mills have started threatening the Government that they would not be able to make payment to the cane-growers and they are asking for a rise in the price of levy sugar as well as of open market sugar. Keeping this in view, may I know from the hon. Minister what steps Government propose to take to ensure to the cane-growers a due return and not give any rise to the sugar mills, not to maintain the rise which has now declined fortunately for the benefit of the consumers?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The answer to this question will be covered by the statement which I will be making just now.

MR. SPEAKER: The Minister is going to make a statement immediately after this. The reply to your question may be covered by that.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: When is he going to make that statement? He has not given a reply to my question.

MR. SPEAKER: A policy statement will be made on the floor of the House this morning. Therefore, it is not proper for him to cover that area now.

You may ask the second supplementary.